population of cattle and buffaloes in Andhra Pradesh is as under:

(in thousand nos.)

(i)	Cross-bred Cattle	486
(ii)	Indigenous Cattle	10461
(iii)	Total Cattle out of which:	10947
	(a) Cows (females)	4734
	(b) bulls (males)	6213
(iv)	She-Buffaloes (Females)	7801
(v)	He-Buffaloes (males)	1352
(vi)	Total Buffaloes	9153

(c) and (d) For breed improvement in animals Government has been following the policy of cross-breeding of low producing indigenous breeds of animals using Artificial Insemination and Embryo Transfer Technology. The Government of India has been providing assistance to the State Governments under the two schemes viz., Extension of Frozen Seman Technology and Progeny Testing Programme and National Bull Production Programme for this purpose. The amount of assistance provided to Andhra Pradesh for breed improvement under Extension of Frozen Seman Technology and Progeny Testing Programme is Rs. 73.89 lakhs during the period 1992-93 to 1995-96. No proposal has been received from State Government under the National Bull Production Programme during the last four years of the 8th Plan.

दुधारू पशुओं को घटिया किस्म का खनिज आहार दिया जाना

2908. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**: क्या पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दुधारु पशुओं को अधिक दुग्ध उत्पादन हेतु घटिया किस्म का डाईकैल्शियमफास्फेट नामक खनिज, जिसमें भारी धातु, सिलिका, आर्सेनिक इत्यादि शामिल हैं, आहार में दिया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन खनिजों के सेवन से पशुओं में "मैड काउ डिज़ीज़" जैसी घातक बीमारियां पैदा हो सकती हैं; जो विदेशों में पहले से ही भयानक रूप से फैल चुकी हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार के खनिजों के उत्पादन एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए कोई कदम उठाने का विचार रखती है?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) डाइकैल्शियमफास्फेट जो पशुधन के आहार के लिए खनिज मिश्रण के मिलाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक अवयव है, में भारती धातु, सिलिका तथा आर्सेनिक आदि शामिल नहीं होते है।

(ख) घटिया किस्म के खनिज मिश्रण के सेवन से "मैड काउ" रोग पैदा नहीं होता। डाइकैल्शियमफास्फेट के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के विशिष्ट मानदंड हैं जिससे उचित गुणवत्ता नियंत्रण का पता लगाने में सहायता मिलती है।

(ग) उक्त भाग (क) तथा (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मवेशियों के लिए चारे तथा औषधियों के उत्पादन के नियंत्रण तथा विनियमन के संबंध में कानून

2909. **श्री राजनाथ सिंह "सूर्य"**: क्या पशु पालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में मवेशियों के लिए चारे तथा औषधियों के उत्पादन के नियंत्रण तथा विनियमन संबंधी कोई कानून नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ऐसे किसी कानून के अभाव में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुधारु पशुओं हेतु घटिया किस्म की दवाएं बाजार में धड़ल्ले से बेची जा रही हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कानून बनाने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक?

पशुपालन और डेयरी विभाग के राज्य मंत्री (डा॰ रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ङ) जी, नहीं। गोपशुओं के लिए औषधियों का उत्पादन तथा बिक्री की औषधि तथा कास्मेटिक अधिनियम, 1940 तथा संगत विनियमों यथा औषधि और कास्मेटिक नियमावली, 1945, औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1987 द्वारा

विनियमित किया जाता है। औषधि तथा कास्मेटिक अधिनियम, 1940 की धारा 3(ख)(i) के अनुसार औषधि की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: "मनुष्यों अथवा पशुओं के आन्तरिक अथवा बाहरी इस्तेमाल के लिए सभी औषधियों और मनुष्यों तथा जानवरों में किसी बीमारी अथवा विकार का पता लगाने, उसका उपचार करने उसका प्रशमन अथवा निवारण करने के लिए अभिप्रेत सभी पदार्थ जिसमें मच्छरों जैसे कीड़ों के निवारण के प्रयोजन के लिए लागू की गई तैयारियां शामिल है।" इसी प्रकार गोपशु चारा एक ऐसी मद है जो अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत शामिल है।

Setting of Target for Milk Cooperatives for the Ninth Plan

2910. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that at conference of State Ministers of Animal Husbandry, a target of one lakh milk cooperatives has been set for the Ninth Plan;

(b) whether it is also a fact that during the last 50 years only 50,000 milk cooperatives could be set up;

(c) if so, the reasons for setting such a high target for the Ninth Plan;

(d) whether it is also a fact that doubts have been expressed by the experts in the field such as, Dr. Kurian;

(e) whether Government would like to revise the targets; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING (DR. RAGHUVANSH PRASAD SINGH): (a) A conference of State Ministers of Animal Husbandry and Dairying recommended formation of one lakh dairy cooperatives during the Ninth Plan.

(b) About 90,000 dairy cooperative societies have been organised in the country under various State Government and Central Government schemes upto 31-12-96.

(c) There are a large number of villages not only in the non-operation Flood districts, but also in operation flood districts which produce or have the potential to produce milk to a level that can sustain a viable dairy cooperative structure. The Government feels that it is necessary to organise dairy cooperatives in these villages so that benefits of dairy devlopment through cooperatives flow to the poor landless labourers and small/marginal farmers in those villages also.

(d) No expert in the field has expressed any doubt. The National Dairy Development Board (NDDB) has also not conveyed any doubt or for that matter any view to the Government in the matter. In fact the Technology Mission on Dairy Development which is being implemented by the NDDB had in 1988 targeted formation of an additional 80,000 dairy cooperatives over and above the target of the Operation Flood Programme.

(e) and (f) Keeping in view the felt need to help the poor farmers, landless labourers and other weaker sections of rural population to earn an additional income through dairying with the support of dairy cooperatives, the Government would endeavour to go by the recommendations of the State Ministers' Conference.

उर्वरकों की उत्पादन लागत में वृद्धि

2911. श्री चीमनभाई हरीभाई: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1996-97 के दौरान उर्वरकों की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दिए जाने के बावजूद अनेक उर्वरक इकाइयां रुग्ण होती जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि हीं, तो उसके क्या कारण है; और